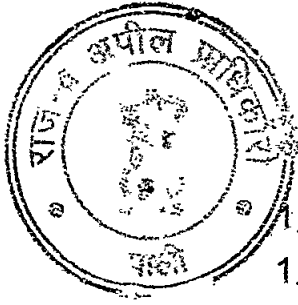


न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2016 G.C.M.S. No. 2016/00493 दर्ज दिनांक : 15.07.2016
अपीलार्थिगणः

1. मृतक प्रभु पुत्र माला के कायम मुकाम—
 - 1/1 मंशाराम पुत्र प्रभू
 - 1/2 मांगीलाल पुत्र प्रभू
 - 1/3 बाबुलाल पुत्र प्रभू, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
 - 1/4 लक्ष्मणराम पुत्र प्रभू, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली के कायम मुकाम—
 - 1/4/1 गोविंद पुत्र स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/2 आकाश कुमार पुत्र स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/3 ममतादेवी पुत्री स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/4 मंजू देवी पुत्री स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/5 शास्दादेवी पुत्री स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/6 वीणादेवी पुत्री स्व. लक्ष्मणराम
 - 1/4/7 अमरती पत्नि स्व. लक्ष्मणराम, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
 - 1/5 फुलीबेन पुत्री प्रभू
 - 1/6 शांतिबाई पुत्री प्रभू
 - 1/7 भागु बाई पुत्री प्रभू
 - 1/8 गेंदीबाई बेवा प्रभू, फौत जिसके विधिक वारिसान अपीलांट मौजूदा है, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

**बनाम****प्रत्यर्थिगणः**

1. मृत रता पुत्र भीखा, जाति मेघवाल, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली के का.मु.—
 - 1/1 विनोदकुमार पुत्र रता
 - 1/2 अरविंदकुमार पुत्र रता
 - 1/3 गजीदेवी बेवा रता जातिगण मेघवाल, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
 - 1/4 भंवरीदेवी पुत्री रता पत्नि हस्पाली, जाति मेघवाल, निवासी राजपुरा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. खंगारा पुत्र भीखा
3. विसा पुत्र भीखा, जातिगण मेघवाल, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
4. तौलिया पुत्र अमरा के का.मु.—
 - 4/1 तोजाराम पुत्र तौलिया
 - 4/2 फुटरमल पुत्र तौलिया
 - 4/3 गलबाराम पुत्र तौलिया, तमाम जातिगण मीणा, निवासीगण धीपली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नाड़ी, मीणों का बास, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

5. जेसा पुत्र अमरा, जातिगण मीणा, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

6. झुंझा पुत्र नवा के कायम मुकाम—

6/1 चौपा पुत्र झुंझा

6/2 नोपा पुत्र झुंझा, जातिगण मीणा, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 150/2002 बअनवान मृतक प्रभू के का.मु. मंशाराम वगैरह बनाम रता वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2009 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री वीरमाराम मीणा, श्री जितेन्द्रसिंह सठौड़, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 150/2002 बअनवान मृतक प्रभू के का.मु. मंशाराम वगैरह बनाम रता वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2009 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधिन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई मौका नहीं दिया जो नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है। अपीलांट ने अपने खातेदारी हक हकूक लेने के लिये वर्ष 1996 में दावा प्रस्तुत किया जो दावा लगातार 13 साल तक चला केवल पक्षकार बनने की दरखास्त का निर्णय किया एवं जबाबुल जबाब पेश करने के लिये पेशियां चलती रही और बिना पत्रावली साक्ष्य में आये ही दावा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया जिससे अपीलांट अपने मौलिक हक अधिकार से वंचित हो गया है इस कारण उक्त पत्रावली को वापस सुनवाई हेतु भेजे जाने व अदम हाजरी अदम पैरवी के निर्णय को निरस्त करना न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप रहेगा। अधिवक्ता की लापरवाही के कारण मुकदमा खारिज हुआ है। अधिवक्ता का दायित्व था कि वो पेशी पर जाते ओर अगर उनको असुविधा थी तो अपीलांट को नोटिस देते लेकिन न तो अपीलांट को इत्तला की ओर न ही स्वयं ही उपस्थित हुये ओर जब भी अपीलांट पूछते तो केवल अधिवक्ता

ये ही कहते कि आपकी जरूरत होगी तब बुला लेंगे ओर इस तरह विश्वास में रखते हुये लापरवाही करके अपीलांट के मुकदमे को अधिवक्ता जो अपीलांट की ओर से विधिक तौर पर अधिकृत थे और उन्होंने लापरवाही बरतकर मुकदमा खारिज करवाया है। जिससे अपीलांट अपने वैधानिक हक अधिकार से वंचित रहा है ऐसे निर्णय को अपास्त किया जाना लाजमी है। अपीलाधिन निर्णय दिनांक 09.07.2009 की जानकारी सर्वप्रथम तारीख 03.07.2016 को तब हुई जब अपीलांट मुम्बई से अपने घर आये ओर कुंए व जमीन पर जाने लगे तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि यह जमीन सिवाय चक हो गई है तब अपीलांट ने तारीख 04.07.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने यह जमीन सिवाय चक के साथ साथ इस मुकदमे का फैसला होना भी बताया तब अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर इस निर्णय की नकल हेतु आवेदन संख्या 316 पेश किया जो तारीख 06.07.2016 को नकले मिली ओर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील पत्र तैयार करवाया जो जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की

जाकर रैस्पॉडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तालब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण रैस्पॉडेंट के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए व बंटवाड़ा बाबत वादपत्र दिनांक 30.01.1996 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2009 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.07.2016 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधिन निर्णय दिनांक 09.07.2009 की जानकारी सर्वप्रथम तारीख 03.07.2016 को तब हुई जब अपीलांट मुम्बई से अपने घर आये ओर कुंए व जमीन पर जाने लगे तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि यह जमीन सिवाय चक हो गई है तब अपीलांट ने तारीख 04.07.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने यह जमीन सिवाय चक के साथ साथ इस मुकदमे का फैसला होना भी बताया तब अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर इस निर्णय

की नकल हेतु आवेदन संख्या 316 पेश किया जो तारीख 06.07.2016 को नकले मिली ओर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील पत्र तैयार करवाया जो जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वादीगण थें तथा प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। पक्षकारान का यह दायित्व होता है कि वह अपने अधिवक्ता से नियमित संपर्क में रहें तथा विचाराधीन प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में निरंतर जागरूक रहें। अपीलांट्स द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 04.07.2016 को संपर्क किया, तब उनके अधिवक्ता ने मुकदमे का फैसला होना बताया। जिससे प्रथम बार जानकारी हुई। अर्थात यह स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट द्वारा दिनांक 09.07.2009 से दिनांक 04.07.2016 के मध्य दीर्घ अवधि तक अपने अधिवक्ता से कोई संपर्क नहीं किया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्राप्त की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण लंबे समय से वादी से अपेक्षित जवाबुलजवाब हेतु नियत रही। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट्स वादीगण द्वारा जानबूझकर एवं लापरवाहीपूर्वक विलंब कारित किया तथा प्रकरण में लगभग 7 वर्ष अर्थात लगभग 2555 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया। जिसे किसी भी दृष्टि से युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-
condonation of delay-in-ordinate delay of 3320 days in filing
appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court
can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason
given to condone the inordinate delay-Held, Order is not
sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 –
Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or
indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be

adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.



4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of

equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

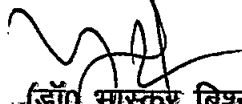
5. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान हैं तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 2555 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रुख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 2555 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलासा सुनाया गया।


(डॉ० मास्कर विनोद)
राजस्व अपील अधिकारी, पाली